This increase was necessitated due to sharp increase in input costs. There is no statutory control over the price of indigenous newsprint. The import of newsprint has also been decanalised w.e.f. 1-4-92. The newsprint industry can import one kg. of standard newsprint for every 2 kgs. of indigenously produced newsprint purchased by them.

Sick Industries in Marathwada industrial estates

203. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of sick industries in the Marathwada industrial estates and what are the reasons indentified for their sickness;

(b) whether, there is a general complaint by the entrepreneurs about the rampant corruption in the MSEB, MIDC, District Industries Centre etc. hampering the pace of industrialisation in Marathwada; and

(c) if so, what steps have been taken by Government in the direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) According to Reserve Bank of India, 15 industrial units in the non-small scale sector were sick as at the end of September, 1990 in the Marathwada region of the State of Maharashtra. Similar information in respect of sick industrial units in the small scale sector is not maintained centrally.

The main reasons for sickness in Marathwada as reported by banks related to managerial, financial and labour problems, non-availability of raw material, defective planning and technical viability and fall in domestic and export demands.

(b) and (c) According to available information, no such general complaint has been lodged by entrepreneurs with the Ministry of Industry against Maharashtra State Electricity Board, Maharashtra State Industrial Development Corporation or District Industries Centres.

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया निवेश

204. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 तक महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया ;

(ख) इन उपक्रमों में प्रति वर्ष कितना लाभ/घाटा हुआ और इन में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) महाराष्ट्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन में केन्द्रीय सरकार का निवेश करने का प्रस्ताव है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 28 उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं। 31-3-1991 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में किया गया पूंजीनिवेश तथा कर्मचारियों की संख्या तथा वर्ष 1990-91 के दौरान हुए शुद्ध लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है [नीचे देखिए]

(ग) केन्द्रीय परियोजनाओं में पूंजी-निवेश, परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।